एक का नाम है "गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, वर्कर्स यूनियन, अलीगढ़" तथा दूसरी है "दी राजकीय प्रैस, अलीगढ़"। पहले वाली अमान्यता-प्राप्त यूनियन है किन्तु वह फैडरेशन आफ वर्कर्स आफ दि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेसेज से सम्बद्ध है जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है।

(ख) और (ग). गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस वर्कर्स यूनियन के उपाध्यक्ष अनेक बार विदेश गये हैं। यह आरोप कि उन्हें विदेशों से बहुत धन मिलता है, प्रमाणित नहीं किया जा सका। उनका विदेशी बैंकों में कोई हिसाब (एकाउन्ट) है इसकी जानकारी सरकार को नहीं है।

(घ) 1961 में भारत वापस आने पर पालम हवाई अड्डे पर उनकी तलाशी ली गयी थी। डायरेक्टर आफ एन्फोर्समेंट के द्वारा फारेन एक्सचेंज रेग्यूलेशन के अन्तर्गत न्यायिक-निर्णय की कार्यवाई की गयी। उनके विरुद्ध कोई विभागीय आरोप विचाराधीन नहीं है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, अलीगढ़

5533. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री आत्म दास :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :

क्या निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रेस, अलीगढ़ के यांत्रिक विभाग के मुख्य मिस्त्री के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उसकी अदक्षता के परिणामस्वरूप उत्पादन में भारी हानि हो रही है; और

(ग) यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़ के हैड मैकेनिक के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये गये हैं।

(ख) और (ग): आरोपों की अभी तक जांच की जा रही है।

गवर्नमेंट आफ इण्डिया प्रेस, अलीगढ़

5534. **श्री राम गोपाल शालवाले :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री :
श्री शिव कुमार शास्त्री :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री हुकम चन्द कछवाय :
डा० सूर्य प्रकाश पुरी :
श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री यशवन्त सिंह कुशवाह :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अलीगढ़ स्थित गवर्नमेंट आफ इंडिया प्रैस के भूतपूर्व मैनेजर पर दवाइयों में मिलावट करने और जाली रसीद बनाने के गम्भीर आरोप लगाये गये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त व्यक्ति के विरुद्ध मामला बहुत समय से मुख्य नियंत्रक के कार्यालय में विचारार्थ पड़ा हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और सरकार का इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) भारत सरकार मुद्रणालय के भूतपूर्व प्रबन्धक के विरुद्ध मैडीकल क्लेम को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में अनियमितता के आरोप लगाए गए थे। किन्तु दवाइयों में मिलावट के सम्बन्ध में कोई आरोप नहीं लगाया गया ।

(ख) तथा (ग). आरोपों की जांच लगभग पूरी होने को है। कुछ देरी अवश्यम्भावी थी क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के डाक्टरों (मैडीकल अथारटीज़) से परामर्श करना था।

Grants to Medical Colleges

5535. Shri S. A. Agadi: Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Grants or aids are given to the Medical Colleges run by the States in addition to the Grant-in-aid given for establishing these Institutions; and

(b) if so, the amounts so given, State-wise since 1950 and the admission capacity of the colleges, State-wise?

The Minister of Health and Family Planning (Dr. S. Chandrasekhar): (a) Central assistance is made available to State Governments, for the establishment and expansion of medical colleges in accordance with an approved pattern, both for recurring as well as non-recurring expenditure using each seat as the unit. This covers the cost of buildings and equipment needed for the establishment of the college as also a recurring grant per seat for staff and other recurring items.

(b) The Scheme for the establishment of new medical colleges was started with effect from 1956-57 in the Second Five Year Plan. Except for the first two years, grants for the new colleges are being released on group basis for various Plan schemes together. As such the information in respect of the quantum of such assistance given to different State Governments from 1950 onwards cannot be furnished readily.

A statement showing the admission capacity of different Colleges in the country in the year 1966-67 is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-1029/67].

कम आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के निकट क्वार्टर देना

5536. श्री मोहन प्रसाद :
श्री रवि राय :
श्री महाराज सिंह भारती :

क्या **निर्माण, आवास तथा पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार कम आय वर्ग के सरकारी कर्मचारियों को उनके कार्यालयों के निकट क्वार्टर देने का है;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार उन कर्मचारियों को उनके कार्यालयों से मीलों दूर क्वार्टर देती है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। यह व्यवहारिक प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बहुधा सामान्य पूल वास कार्यालय से कुछ दूर स्थित होते हैं। जहां यह व्यवस्था संभव है जैसे रामकृष्णपुरम अथवा लाल किले तथा पुराने सचिवालय के मध्य वहां कार्यालय के निकटस्थ रिहायशी वास लेने का विकल्प पहले ही से है।